



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 165]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 22, 2009/वैशाख 2, 1931

No. 165]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 22, 2009/VAISAKHA 2, 1931

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2009

विषय : चीन जन. गण. और इजरायल के मूल के या वहाँ से निर्यातित एसडीएच ट्रांसमिशन उपकरण के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत

फा.सं. 14/2/2009डीजीएडी.—चूंकि मै. तेजस नेटवर्क्स लि. (जिसे एतदपश्चात् आवेदक कहा गया है) ने वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात् अधिनियम कहा गया है) और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात् नियमावली कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे एतदपश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन जन. गण. और इजरायल (जिन्हें एतदपश्चात् "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित एसडीएच ट्रांसमिशन उपकरण (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध वस्तु कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाया है और संबद्ध वस्तु की पाटनरोधी जांच शुरू करने और पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

2. और चूंकि प्राधिकारी ने यह पाया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति और पाटन तथा क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य विद्यमान है, अतः प्राधिकारी आरोपित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने के लिए और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाता है तो वह घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, के लिए उक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसार आरोपित पाटन ओर घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की एतद्वारा जांच शुरू करते हैं।

विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद सिंक्रोनस डिजिटल हायआर्की ट्रांसमिशन उपकरण, उसके पुर्जे, संबंधित सॉफ्टवेयर और उसके अनिवार्य भाग तथा संघटक हैं जो सीकेडी तथा एसकेडी रूप में संयोजित हैं या एवेन्चुअल ब्रॉड बैंड/सेल्युलर उपकरण के साथ फिट किए गए हैं। एसडीएच ट्रांसमिशन उपकरणों को मल्टीप्लैक्सर्स, एंड ट्रॉप मल्टीप्लैक्सर्स (एडीएम), मल्टीपल एंड ड्रॉप मल्टीप्लैक्सर्स (एमएडीएम), डिजिटल क्रास-कनेक्टर्स के नाम से भी जाना जाता है।

4 एसडीएच ट्रांसमिशन उपकरण आदि के लिए नियत लोकप्रिय पीसीबी, विद्युत आपूर्ति, लेजर, चेंसिस तथा सॉफ्टवेयर में एसडीएच ट्रांसमिशन उपकरण के अनिवार्य भाग शामिल होते हैं और वे विचाराधीन उत्पाद के दायरे में आते हैं। तथापि ये संघटक तभी विचाराधीन उत्पाद के दायरे में आते हैं जब उक्त संघटक एसडीएच ट्रांसमिशन उपकरणों के अनुप्रयोग के लिए हों।

5. एसडीएच ट्रांसमिशन उपकरणों की खरीद ट्रांसमिशन उपकरण के रूप में या अन्य उपकरण अर्थात् ब्रॉडबैंड और/अथवा सेल्युलर (जीएसएम एवं सीडीएमए, दोनों) उपकरणों के भाग रूप में की जा सकती है। ब्रॉड बैंड और/अथवा सेल्युलर उपकरणों के भाग स्वरूप एसडीएच ट्रांसमिशन उपकरण भी विचाराधीन उत्पाद के दायरे में आते हैं।

6. विचाराधीन उत्पाद का आयात पूर्ण उपकरण के रूप में या फिर एसकेडी अथवा सीकेडी रूप में किया जा सकता है। इसके अलावा, नेटवर्क में एसडीएच ट्रांसमिशन उपकरण को जोड़ने/स्थापित करने के लिए अनेक सहायक उपकरणों (ई1 केबल, पीसीएम केबल, पावर केबल, रैक, वर्कस्टेशन) की जरूरत होती है। सॉफ्टवेयर इन उपकरणों का अभिन्न भाग होता है जिसकी खरीद या तो उपकरण के एक भाग के रूप में या फिर अलग-अलग की जा सकती है। ये सभी विचाराधीन उत्पाद के दायरे में तब आते हैं जब इनका आयात एसडीएच ट्रांसमिशन उपकरण के रूप में किया गया हो। विचाराधीन उत्पाद सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 85 के अंतर्गत वर्गीकृत है। भारतीय व्यापार वर्गीकरण के अनुसार यह सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची 1 के शीर्ष 8517.62 के अंतर्गत पुनः वर्गीकृत है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जाँच के दायरे पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है।

घरेलू उद्योग का आधार

7. यह आवेदन तेजस नेटवर्क्स लि., बंगलौर द्वारा दायर किया गया है जो भारत में संबद्ध उत्पाद का एक प्रमुख उत्पादक है। भारत में इस उत्पाद के चार अन्य उत्पादक हैं। याचिका का समर्थन मेजरमेंट एंड कंट्रोल लि. द्वारा किया गया है। प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया है कि (क) आवेदक का उत्पादन भारतीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा; (ख) आवेदन का स्पष्ट रूप से समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादकों का उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान उत्पाद के उत्पादन के 50% से भी अधिक बनता है; और (ग) यह आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किया गया है।

8. उपर्युक्त की जांच करने के बाद प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि आवेदक नियम 2 के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है और आवेदन में उपर्युक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसार आधार संबंधी मानदंड की पूर्ति होती है।

शामिल देश

9. वर्तमान जांच में शामिल देश चीन जन. गण. और इजरायल हैं और इसलिए इन्हें वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ संबद्ध देश कहा जाएगा।

समान वस्तु

10. आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तुओं में कोई विशेष अंतर नहीं है। इस उत्पाद का आयात आयातकों और उपभोक्ताओं द्वारा किया जा रहा है। उपभोक्ताओं द्वारा घरेलू एवं आयातित उत्पाद का उपयोग अदल-बदल कर किया जा रहा है। आवेदक का दावा है कि दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद सभी अनिवार्य विशेषताओं के रूप में समनुरूप हैं और इस प्रकार ये नियमावली के अर्थ के भीतर समान वस्तुएं

हैं। वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु को उपर्युक्त नियमावली के अर्थ के भीतर संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद के समान वस्तु माना जा रहा है।

सामान्य मूल्य

11. आवेदक ने दावा किया है कि चीन को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला व्यवहार दिया जाना चाहिए और सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में उत्पादन लागत के आधार पर किया जाए। इजरायल के मामले में आवेदक ने इजरायल में सामान्य मूल्य का निर्धारण एसजीए तथा लाम सहित परिकलित उत्पादन लागत के आधार पर किया है।

12. आवेदक ने सुझाव दिया है कि संबद्ध वस्तु का उत्पादन और उसकी बिक्री अमरीका तथा यूरोप में की जाती है और इन देशों को चीन हेतु एक प्रतिनिधि देश के रूप में माना जा सकता है। आवेदक ने इन देशों में उत्पादकों के नाम और पते प्रस्तुत किए हैं। इस संबंध में हितबद्ध पार्टियों को अपने अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

13. विचाराधीन उत्पाद के प्रत्येक मॉडल के लिए अलग से सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है। नियमानुसार पाटनरोधी जाँच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए सामान्य मूल्य के बारे में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है।

निर्यात कीमत

14. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के निर्यात कीमत का निर्धारण भारत में विचाराधीन उत्पाद के वास्तविक ज्ञात आयातकों पर विचार करने के बाद किया गया है। सीआईएफ आयात कीमत के 10% की दर से कीमत समायोजनों का दावा किया गया है। तथापि, आवेदक ने दावा किया है कि यदि कीमत समायोजनों की अनुमति नहीं दी जाती है तो पाटन मार्जिन काफी अधिक होगा।

15. विचाराधीन उत्पाद के प्रत्येक मॉडल के लिए अलग से निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है। नियमानुसार पाटनरोधी जाँच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए निर्यात कीमत के बारे में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है।

पाटन मार्जिन

16. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाने स्तर पर की गई है जिससे संबद्ध देशों के संबंध में अत्यधिक पाटन मार्जिन का पता चलता है।

17. इस बात का पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना निर्यात कीमत से काफी अधिक है जिससे प्रथम दृष्ट्या यह पता चलता है कि संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तु का भारतीय बाजार में पाटन किया जा रहा है।

18. आवेदक ने तर्क दिया है कि पाटनरोधी मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी को संगत अवधि के दौरान विदेशी उत्पादकों को ग्राहकों द्वारा दिए गए उन ऑर्डरों पर विचार करना चाहिए जिन पर आपूर्तियाँ संगत अवधि के दौरान पूरी नहीं हुई हैं। आवेदक ने दावा किया है कि दिए गए ऑर्डर “की गई बिक्री” के द्योतक हैं जिन पर आपूर्तियाँ यथासमय की जाएंगी। आवेदक ने तर्क दिया है कि उस उत्पाद की बिक्री की वास्तविक शर्त उपभोक्तों द्वारा प्रदत्त ऑर्डर

है और प्रस्तावित अवधि के बाद में की गई आपूर्तियाँ कम महत्व रखती हैं। तथापि, प्राधिकारी ने इस चरण पर केवल ग्राहकों द्वारा प्रदत्त ऑर्डरों और संगत अवधि के दौरान की गई ज्ञात आपूर्तियों के आधार पर ही पाटन मार्जिन का निर्धारण किया है। हितबद्ध पार्टियाँ पाटन मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ दिए गए ऑर्डरों और पूरी न की गई आपूर्तियों सहित उनकी उपयुक्तता के बारे में अपने अनुरोध कर सकती हैं।

क्षति एवं कारणात्मक संबंध

19. आवेदक ने वास्तविक क्षति से संबंधित विभिन्न मापदंडों के बारे में सूचना प्रस्तुत की है। बाजार हिस्से में गिरावट, आयातों में समग्र रूप में और भारत में उत्पादन एवं खपत की तुलना में अत्यधिक वृद्धि, अत्यधिक कीमत कटौती, जिससे कीमत ह्रास हुआ है, कम कीमत पर बिक्री, लाभप्रदता में गिरावट, निवेश पर आय, नकद प्रवाह में गिरावट जैसे मानदण्डों से सामूहिक और संचयी रूप से यह पता चलता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटन के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

पाटनरोधी जांच की शुरुआत

20. पूर्वोक्त पैराग्राफों को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल की या वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आरोपित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव की पाटनरोधी जांच शुरू करते हैं।

जांच अवधि

21. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि अप्रैल- दिसंबर, 2008 (नौ माह) तक की है। तथापि, क्षति जांच अवधि में वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 की अवधि और जांच अवधि शामिल होगी।

भूतलक्षी आधार पर शुल्क लागू करना

22. आवेदक ने इन आधारों पर भूतलक्षी प्रभाव से शुल्क लगाने का अनुरोध किया है कि पाटन काफी पहले से हो रहा है, निर्धारित पाटन मार्जिन भी काफी अधिक है, निर्यातकों की जानकारी में यह बात भली-भाँति रही है कि उनके द्वारा पाटन किया जा रहा है और आयातक इस बात से पूर्णतः वाकिफ हैं/होने चाहिए कि निर्यातकों द्वारा पाटन किया जा रहा है। तुलनात्मक रूप से अल्प अवधि में भारी मात्रा में आयात हुए हैं और घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति में वृद्धि हो रही है।

23. उपर्युक्त के आधार पर प्राधिकारी यह मानते हैं कि भूतलक्षी प्रभाव से शुल्क लगाने को न्यायोचित ठहराने का पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य है। हितबद्ध पार्टियों से इस संबंध में अनुरोध करने का आग्रह किया जाता है।

सूचना प्रस्तुत करना

24. संबद्ध देशों के निर्यातकों और भारत में उनके दूतावास के माध्यम से उनकी सरकारों, भारत में ज्ञात संबद्ध आयातकों घरेलू उद्योग को संबंधित सूचना निर्धारित प्रारूप में और निर्धारित ढंग से प्रस्तुत करने और अपने विचारों से निम्नलिखित को अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है :-

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
भारत सरकार
कमरा नं. 240, उद्योग भवन
नई दिल्ली-110107

25. उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(5) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जांचाधीन वस्तु के औद्योगिक प्रयोक्ताओं और उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों को अवसर भी प्रदान किया जा रहा है जो पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में जांच से संगत सूचना प्रस्तुत कर सकते हैं। कोई अन्य हितबद्ध पार्टी भी नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर तथा निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से जांच से संगत सूचना प्रस्तुत कर सकती है।

समय सीमा

26. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना लिखित में प्रस्तुत की जानी चाहिए ताकि वह निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राप्त हो जाए। तथापि जिन ज्ञात निर्यातकों और आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है उनके लिए अलग से उन्हें लिखे गए पत्र की तारीख से चालीस दिनों की अवधि के भीतर सूचना प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

सूचना प्रस्तुत करना

27. नियम 6(7) के अनुसार हितबद्ध पार्टियों से अपेक्षित है कि वे प्राधिकारी को प्रदत्त गोपनीय सूचना का अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करें और यदि ऐसी सूचना देने वाले पार्टी की राय में ऐसी सूचना का सारांश नहीं बनाया जा सकता हो, तो उसके कारणों का विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

28. जहाँ कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना प्रस्तुत करने से मना करता है अथवा अन्यथा उचित अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं करता अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं, जिन्हें वे उपयुक्त समझते हों।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

29. नियम 6(7) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी एक सार्वजनिक फाइल रखते हैं। कोई भी हितबद्ध पार्टी अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय पाठ वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

1536 GI/09-2

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)
INITIATION NOTIFICATION
New Delhi, the 21st April, 2009

No. 14/2/2009-DGAD.— Whereas M/s. Tejas Networks Limited, (herein after referred to as applicant) have filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 (herein after referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (herein after referred to as the Rules), alleging dumping of SDH Transmission Equipment (herein after referred to as subject goods), originating in or exported from the China PR and Israel (herein after referred to as “subject countries”) and requested for initiation of Anti Dumping investigations for levy of anti dumping duties on the subject goods.

2. AND WHEREAS, the Authority finds that sufficient prima facie evidence of dumping of the subject goods from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between the dumping and injury exist, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping and consequent injury to the domestic industry in terms of the Rules 5 of the said Rules to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

PRODUCT UNDER CONSIDERATION

3. Product under consideration in the present petition is Synchronous Digital Hierarchy Transmission Equipment, its accessories, associated software and its essential parts and components, in assembled, CKD, and SKD form or fitted with eventual broadband/cellular equipment. SDH transmission equipments are also known as multiplexers, Add Drop Multiplexers (ADM), Multiple Add Drop Multiplexer (MADM), digital cross-connects

4. Populated PCBs, power supply, lasers, chassis and software meant for SDH transmission equipment, etc. consist of essential parts of SDH transmission equipment and are within the scope of the product under consideration. However, these components are within the scope of the product under consideration only if the said components are meant for SDH transmission equipment application.

5. SDH transmission equipments can be bought either as transmission equipment or forming part of another equipment e.g., broadband and/or cellular (both GSM and CDMA)

equipment. SDH transmission equipments forming part of broadband and/or cellular equipment are also within the scope of the product under consideration.

6. The product under consideration can be imported either as complete equipment, or in SKD or CKD form. Further, a number of accessories are required for connecting/installing SDH transmission equipment in the network (E1 cables, PCM cables, power cables, racks, workstations etc.). Software is an integral part of these equipment, which may be bought either as a part of the equipment or separately. These all are also within the scope of the product under consideration only if imported as part of SDH transmission equipment. The product under consideration is classified under Chapter 85 of the Customs Tariff Act, 1975. It is further classified under the heading 851762 of schedule-I of Custom Tariff Act as per Indian Trade Classification. The classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

DOMESTIC INDUSTRY STANDING

7. The application has been filed by Tejas Networks Limited, Bangalore, who is the major producer of the subject product in India. There are four other producers of the product in India. The petition is supported by Measurement & Control Limited. The Authority has determined that (a) production of the applicant constitutes a major proportion in Indian production; (b) domestic producers expressly supporting the application account for significantly more than 50 percent of production of the like product produced by the domestic industry; and (c) the application has been made by or on behalf of the domestic industry.

8. The Authority after examining the above, determines that the applicant constitutes domestic Industry within the meaning of the Rule 2 and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 of the Rules supra.

COUNTRIES INVOLVED

9. The countries involved in the present investigation are China PR and Israel, and therefore will be referred to as Subject Countries for the purposes of present investigation.

LIKE ARTICLE

10. The applicant has claimed that there is no difference in the subject goods produced by the domestic industry and the subject product imported from the subject countries. The product is being imported by the importers and consumers. The consumers are using the domestic and imported product interchangeably. Applicant has claimed that the two are technically and commercially substitutable. The products produced by the domestic industry and imported from the subject country are identical in all essential characteristics and therefore, are like articles within the meaning of the Rules. For the purpose of the present investigation, the product produced by the applicant is being treated as like article to the product imported from the subject countries within the meaning of Rules supra.

NORMAL VALUE

11. The applicant has claimed that China should be treated as non market economy and the normal value in China may be based on cost of production in India. In case of Israel,

applicant has determined normal value in Israel based on constructed cost of production, including SGA and profit.

12. Applicant has suggested that subject product is produced and sold in USA and Europe and these countries can be treated as surrogate country for China. Applicant has furnished names and addresses of the producers in these countries. Interested parties are invited to make their submissions in this regard.

13. Normal value has been determined separately for each model of the product under consideration. There is sufficient evidence with regard to normal value to justify initiation of an anti-dumping investigation in terms of the Rules.

EXPORT PRICE

14. Export price of the subject goods from the subject countries has been determined by considering actual known imports of the product under consideration in India. Price adjustments have been claimed @ 10% of the CIF import price. The applicant has however claimed that even if price adjustments are not allowed, the dumping margins are significantly high.

15. Export price has been determined separately for each model of the product under consideration. There is sufficient evidence with regard to Export Price to justify initiation of an anti-dumping investigation in terms of the Rules.

DUMPING MARGIN

16. Normal values and export prices have been compared at ex-factory level, which shows significant dumping margin in respect of the subject countries.

17. There is sufficient evidence that the normal value of the subject goods in subject countries is significantly higher than the ex-factory export price indicating, prima facie, that the subject goods are being dumped by exporters from the subject countries into the Indian market.

18. Applicant has argued that the Authority should consider the orders placed by the consumers on the Foreign Producers during the relevant period, against which the supplies have not been completed during the relevant period, for the purpose of determination of dumping margin. Applicant argued that these orders placed represent "sale made" against which the supplies would be affected in due course. Applicant has argued that material term of sale in this product is the order placed by the consumers and the fact of supplies made subsequent to the proposed period is of little consequence. The Authority has however at this stage determined dumping margin only on the basis of orders placed by the consumers and supplies known to have been effected during the relevant period. The interested parties may make their submissions with regard to appropriateness of including orders placed and supplies not completed for the purpose of determination of dumping margin.

INJURY AND CAUSAL LINK

19. The applicant has furnished information on various parameters relating to material injury. Parameters such as decline in market share, significant imports in absolute terms as

also relative to production and consumption in India, significant price undercutting leading to price depression in the market, price underselling, decline in profitability, return on investments and cash flow prima facie collectively and cumulatively indicate that the domestic industry has suffered material injury on account of dumping of subject goods from subject countries.

INITIATION OF ANTI DUMPING INVESTIGATIONS

20. The Designated Authority, in view of the foregoing paragraphs, initiates anti-dumping investigations into the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

PERIOD OF INVESTIGATION (POI)

21. The period of Investigation for the purpose of the present investigation is April-Dec 2008 (9 months). The injury investigation period will, however, cover the period 2005-06, 2006-07 2007-08 and the POI.

IMPOSITION OF DUTY ON RETROSPECTIVE BASIS

22. The applicant has requested for retrospective imposition of duty on the grounds that there is history of dumping, dumping margin determined are too significant, exporters are well aware that they are resorting to dumping and imports are/should be well aware that the exporters are dumping. There is massive imports volume in relatively short period and injury to the domestic industry is aggravating.

23. On the basis of the above, Authority considers that there is prima facie evidence justifying imposition of retrospective duty. Interested parties are requested to make submissions in this regard.

SUBMISSION OF INFORMATION

24. The exporters in the subject country, Governments through the Embassies, the importers in India known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Designated Authority at the following address:

The Designated Authority
Directorate General of Anti Dumping & Allied Duties,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce,
Government of India,
Room No. 240, Udyog Bhavan,
New Delhi – 110011.

25. As per Rule 6(5) of Rule supra, the Designated Authority is also providing opportunity to the industrial users of the article under investigation and to representative consumer organizations, who can furnish information relevant to the investigation regarding

1536 G.I/09-3

dumping, injury and causality. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation within the time limit set out below.

TIME LIMIT

26. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are however required to submit the information within forty days from the date of the letter addressed to them separately.

SUBMISSION OF INFORMATION

27. In terms of Rule 6(7) of the Rules, the interested parties are required to submit non-confidential summary of any confidential information provided to the Authority and if in the opinion of the party providing such information, such information is not susceptible to summarization, a statement of reason thereof, is required to be provided.

28. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Designated Authority may record findings on the basis of facts available and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

INSPECTION OF PUBLIC FILE

29. In terms of Rule 6(7), the Designated Authority maintains a public file. Any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by interested parties.

R. GOPALAN, Designated Authority